

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DUNGARPUR (RAJ.)

No. Rev./2017/2761

Dated : 26 July, 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule, Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 6.50 hectare of Forest land proposed to be diverted in favour of irrigation Department Dungarpur for the rehabilitation of Khatedar's affected under construction of Ber Ka Bhatda Dam Minor irrigation Project falls within jurisdiction of "UNTIA" village in Dungarpur Tehsil, District Dunagarpur

It is further certified that:

- j. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.50 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexure.
- k. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.
- l. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agriculture communities.

Inc. - Gram sabha Samiti,
Sub Divisional Samiti,
and Distt. level Samiti


(Rajendra Bhatt)
District Collector
Dungarpur (Raj.)

वनाधिकार अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत जिला वन्य संहिता की बैठक दिनांक 25-07-2017
दिनांक :- 25-07-2017

"अधिशारी अभियान जल संसाधन स्वच्छ प्रथम डूंगरपुर द्वारा बोर का भाटड़ा लक्ष्मी सिंचाई परियोजना शुरू कंट्रिया के बांध निर्माण हेतु अवाप्त शुद्ध भूमि 6-50 हेक्टर के अंतर्गत को विस्थापित करने हेतु शनीयुला वन स्वच्छ चक नं. 19 की 6-50 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार पत्र एवं तत्संबंधी कार्यवाही विचाराधीन होने के बावजूद प्रमाण-पत्र बांधा गया है। उक्त सम्बन्ध में आज दिनांक 25-07-17 को जिला फलबटर डूंगरपुर की अध्यक्षता में वनाधिकार की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

(1) श्री दिलीप शुक्ला सा.का.	सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र ककोडा -
(2) " देवीपाल कटारी	सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र देवलकाम
(3) " लखिनय पाठक R.A.S	सदस्य	अतिरिक्त फलबटर डूंगरपुर
(4) " राम किशन मीणा R.A.S	सदस्य सचिव	प्रशिक्षण अधिकारी (FA) (T.A.D.) डूंगरपुर
(5) " सहायक वन संरक्षक (प्रधान गार्ड)	सदस्य	(A.C.F.) डूंगरपुर

जिला फलबटर डूंगरपुर उरा बोर का भाटड़ा लक्ष्मी सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु अवाप्त शुद्ध भूमि के अंतर्गत को विस्थापित करने हेतु शनीयुला वन स्वच्छ चक नं. 18, 19 की 6-50 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की गई। कुल 6-50 हेक्टर वन भूमि प्राप्त के बदले में शम मत्पवाज में कुल 6-50 हेक्टर भूमि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2755-60 दिनांक 25-07-17 से वन विभाग डूंगरपुर को आवंटित की गई है। उक्त बांध निर्माण के विस्थापितों के पुनर्वास की भूमि 6-50 हेक्टर शम पंचायत कंट्रिया में अवस्थित है। शम पंचायत कंट्रिया की शम सभा बैठक दिनांक 22-07-2017 द्वारा प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की भूमि में वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी दायदार को पट्टा (अधिकार पत्र) जारी नहीं किया है तथा न ही वनाधिकार दावा पट्टा जारी करने का विचाराधीन है। बावजूद प्रस्तावित पट्टा लिया गया। इसी कारण वनाधिकार की उप

वन भूमि पुनर्वास हेतु दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तथा प्रस्तावित वन भूमि 650 ईक्टेयर भूमि पर वर्तमान में अतिरिक्त/कांस्टा नहीं किया है व वनाधिकार अधिनियम 2006, 2008 व संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार दावों में पट्टा (अधिकार पत्र) जारी नहीं हुआ है एवं न ही पट्टा जारी करने सम्बन्धी कोई प्रकरण विचारणीय है।

ग्राम समा समिति व अंटिया एवं उपखण्ड समिति डुंगरपुर में वनाधिकार अधिनियम 2006, 2008 व संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं होने एवं न ही कोई प्रकरण की कार्यवाही विचारणीय होने से वांछित व वनाधिकार प्रमाण पत्र वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक में बैठक सन्मन्यवाद समाप्त की गई।

25.7.17
ADM Durg.

Prashant Garg, ACF

डि. प्र. सं. दुर्गपुर

25/7/17
जिला कलक्टर
दुर्गपुर

POT (TAD)
25/7/17

लिपिकारी।
डि. प्र. सं.
वा. 22 आनोड
25/7/2017

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:- एसडीएम/राजस्व/2017/1230

दिनांक:-24/7/17

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
डूंगरपुरविषय:- बोर का भाटडा बांध निर्माण में अवाप्त भूमि से विस्थापित काश्तकारों को
वनखण्ड रानीझुला में वन भूमि आवंटित करने बाबत।प्रसंग:- ग्राम पंचायत उटिया पं0स0 झोथरी का पत्र क्रमांक 2017-18/36
दिनांक 22.7.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्र में निवेदन है कि बोर का भाटडा बांध निर्माण करने से विस्थापित काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला में भूमि आवंटन करने हेतु ग्राम सभा उटिया द्वारा दिनांक 22.7.2017 को प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी छाया प्रति संलग्न है। ग्राम सभा में विस्थापित काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला के चक नं0 18 एवं 19 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में आवंटन की जाने वाली भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण/ आवंटन नहीं होना बताया जाकर आवंटन हेतु उपयुक्त होना बताया है साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि उक्त भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत पट्टे जारी नहीं हुए हैं एवं पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायत उटिया के प्रासंगिक पत्र में वर्णित विषय के क्र में दि0 24.7.2017 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वनखण्ड रानीझुला के चक नं0 18 एवं 19 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि जो प्रत्यावर्तन के लिये प्रस्तावित है में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत पट्टे जारी नहीं हुए हैं एवं पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अतः पत्र श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्तानुसार कुल किता-5


(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

क्रमांक:- राजस्व/2017/1231-33

दिनांक 24/7/17

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

बोर का भाटडा बांध निर्माण करने के लिए अवाप्त भूमि के कारण विस्थापित काश्तकारों को रानीझुला वनखण्ड के चक 18 व 19 की 6.50 है० भूमि आवंटन करने हेतु उक्त भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तुत है के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आज दिनांक 24.7.2017 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संलग्न सूची अनुसार अधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में अधिष्ठात्री अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 2537 दिनांक 21.7.2017 के अनुसरण में सरपंच/ सचिव राम पंचायत उटियां द्वारा दिनांक 22.7.2017 को ग्रामसभा का आयोजन कर बोर का भाटडा बांध निर्माण कार्य से विस्थापित काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला के चक नं० 18 एवं 19 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि आवंटन करने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रस्ताव में आवंटन की जाने वाली भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण/ आवंटन नहीं होना बताया जाकर आवंटन हेतु उपयुक्त होना बताया है साथ ही यह भी दर्शाया है कि उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के पट्टे जारी नहीं हैं एवं पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग में मौजूद अतिक्रमण रजिस्टर का अवलोकन किया जिससे जाहिर पाया गया कि रानीझुला वनखण्ड की चक 18 एवं 19 की 6.50 है० उक्त भूमि जिसका प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है पर कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नहीं है। पूर्व में उक्त भूमि में के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत पट्टे जारी नहीं हुए हैं एवं वर्तमान में पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।



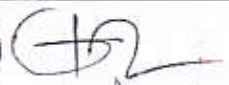
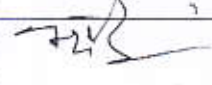
(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

दिनांक.....24/7/17

वनाधिकार/राजस्व/2016 1231-33

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, डूंगरपुर
2. वन संरक्षक डूंगरपुर।
3. विकास अधिकारी पं०स० डूंगरपुर/झाधरी
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, डूंगरपुर
5. मनोनित सदस्य सर्व श्री

बोर का भाटडा बांध निर्माण के संबंध में विस्थापित काश्तकारों को वन खण्ड रानीझुला में वन भूमि आवंटन करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन आज दिनांक 24.7.2017 को किया गया जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया :-

क्र०सं०	नाम अधिकारी/सदस्य	विभाग/पद	वि०वि०/हस्ताक्षर
1	दीपक मेहता	उपखण्ड अधिकारी इंरपुर	
2	रघुवीर सिंह मीना	विकास अधिकारी (फर) झोंथरी	
3	छद्दीलाख पट्टार (क्षेत्रीय)	क्षेत्रीय भवन अधिकारी उग्रखोरे	
4	रूपेन्द्र कुमार परमा	कर्मचारी	
5			

कौमोलीय काम पेचायत इटिगो पेचायत समिति झाबरी

कर्मसं : 2017-2018/36

दिनांक 22/07/20

श्रीमान उपखण्ड अधिक्ता मले

इंजमपुर

विषय :- काम सना (काम पेचायत इटिगो)
मे बौर का बाट्टा बाध निर्माण करने से
विस्थापित कस्बकारों को वन खण्ड राणीजुका
मे वन कुमि आवरण करने हेतु प्रस्ताव
पारित बाबत ।

संदर्भ :- अधिक्ता अधिक्ता जल सेवाओं खण्ड मंत्रम
इंजमपुर के पत्रांक तक्र/2017/2537
दिनांक 21/07/2017 के क्रम मे

मले

निवेदन है कि उपरोक्त पत्र सीपाका
आज दिनांक 22/07/2017 को काम पेचायत इटिगो
मे आगेलित काम सना मे बौर का बाट्टा बाध
निर्माण कार्य से विस्थापित कस्बकारों को
वन खण्ड कुमि राणीजुका से 18.19 मे खण्ड
6.50 हेक्टर कुमि आवरण करने व सर्व सहायि
से प्रस्ताव पारित किया तथा उक्त कुमि पर
वर्तमान मे कोई अतिक्रमण नहीं है, कुमि
आवरण हेतु उपखण्ड एवं खाली है तथा
वर्तमान मे कोई आवरण नही किया गया प्रस्ता
की प्रति संलग्न कर विधि एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु सादर प्रार्थना है ।

काम पेचायत इटिगो

शाम सेवक पदम साधु
काम पेचायत उदरक

